यूपी में सार्वजनिक वाहन इलेक्ट्रिक होंगे

योजना 1

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में सार्वजनिक यातायात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों में उनकी संख्या घटेगी, जो डीजल से चलते हैं। प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है कि सार्वजनिक यातायात के वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य तक प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के सार्वजनिक यातायात को इलेक्ट्रिक मोड में ले जाने की योजना का लक्ष्य रखा है।

यातायात की वजह से बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार अब इस बेड़े में डीजल वाहनों की संख्या में कमी करना चाहती है। फिलहाल, ज्यादातर सार्वजनिक वाहन डीजल से चलते हैं। जानकारों के मुताबिक प्रदेश सरकार केंद्र के सहयोग से इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा बढ़ाएगी। अभी प्रदेश में तकरीबन 800 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही हैं। शहरी निकायों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूपी इलेक्ट्रिक बसों के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मेन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया (फेम) और पीएम ई-बस आदि योजनाओं के तहत मांग प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजेगा। सूत्र बताते हैं कि वर्ष 2030 तक यूपी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 8 हजार तक पहुंचाने की रखी गई है। इसमें पीएम ई-बस सेवा से 2700 बसें हो सकती हैं। यूपी सरकार न केवल सड़क परिवहन बल्कि मेट्रो सेवाओं में भी इजाफा करेगी। इससे लोगों को यातायात में आसानी और सुविधा तो होगी ही, प्रदूषण भी कम होगा।

मखाना प्रोत्साहन के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा

लखनऊ। यूपी में जहां सिंघाड़े की खेती होती है, वहां अब मखाना का भी उत्पादन किया जाएगा। सोमवार को उद्यान, कृषि विपणन राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मखाना विकास योजना उत्तर प्रदेश के किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। यह योजना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन के बाद प्रथम चरण में 10 राज्यों में इसकी योजना लागू की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उन्होंने इस दौरान प्रदेश में मखाना विकास योजना के शुभारम्भ की घोषणा की।

2